

रजिस्ट्रेशननम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्सटूपोस्ट ऐटकन्सेशनलरेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 नवम्बर, 2023 कार्तिक 19, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन कर्जा अनुभाग–3

संख्या 1734/24-3099-80-2022 लखनऊ, 10 नवम्बर, 2023 ———— अधिसूचना

प0आ0-673

चूँकि आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4(4)(ख)(दो), ऐसे प्रयोजन, जैसा कि केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में विहित करे, के लिये स्वैच्छिक आधार पर अधिप्रमाणन कराने की अनुमित प्रदान करती है;

और, चूँिक, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (जिसे आगे "प्राधिकरण" कहा गया है) के परामर्श से सुशासन के लिये आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है) बनायी है जहाँ राज्य सरकार के विभाग के अधीन जो स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक हो, उसके आधार पर प्राधिकरण को संदर्भित किये जाने हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करके प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त कर सकते हैं;

और, चूँिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिको मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञाप संख्या ईएफ0 सं0 13(4)/2020—ईजी—दो(वॉल्यूम—चार), दिनांक 23 मई, 2023 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4(4)(ख)(दो) के साथ पिठत उक्त नियमावली के नियम 5 के निबन्धनों के अनुसार पहचान के प्रयोजनार्थ स्वैच्छिक आधार पर उपभोक्ता एवं नये आवेदक के अधिप्रमाणन एवं ई—के0वाई०सी० हेतु आधार का उपयोग करने के लिये राज्य सरकार की पूर्व सहमित से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को अनुज्ञा प्रदान करने के निमित्त प्राधिकरण का अनुमोदन हस्तान्तरित किया है;

अतएव, अब, उक्त नियमावली के नियम 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 1410/24-3099-80-2022, दिनांक 25 अगस्त, 2023 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश, पावर कॉरपोरेशन लि0 को पहचान के प्रयोजनार्थ विद्युत अपभोक्ता एवं नये आवेदकों हेतु स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन एवं ई—के0वाई0सी0 के उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान करती हैं।

आज्ञा से, महेश कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव। IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1734/XXIV-3099-80-2022, dated November 10, 2023:

No. 1734/ XXIV-3099-80-2022 Dated Lucknow, November 10, 2023

WHEREAS section 4(4)(b)(ii) of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the "said Act") allows performing Aadhaar authentication, on voluntary basis, for such purpose as the Central Government in consultation with the Authority and in the interest of State, may prescribe;

AND, WHEREAS, the Central Government, in consultation with the Unique Identification Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority") has framed the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the "said rules") whereunder the Department of the State Government desirous of utilizing Aadhaar authentication on voluntary basis can seek permission from the Authority by submitting a proposal thereon to the Central Government for making a reference to the Authority;

AND, WHEREAS, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India *vide* Office Memorandum eF. No. 13(4)/2020-EG-II(Vol-IV), dated 23rd May, 2023 has conveyed the approval of the Authority to allow the Uttar Pradesh Power Corporation Limited to use Aadhaar for authentication and e-KYC of consumer or new applicant, on voluntary basis, with prior concurrence of the State Government for the purpose of identification in terms of rule 5 of the said rule *read* with section 4(4)(b)(ii) of the said Act;

Now, Therefore, in exercise of the powers under rule 5 of the said rules, and in supersession of notification no. 1410/24-3099-80-2022, dated August 25, 2023, the Governor is pleased to allow Uttar Pradesh Power Corporation Limited to use Aadhaar authentication and e-KYC on voluntary basis for electricity consumers and new applicants for the purpose of identification.

By order, MAHESH KUMAR GUPTA, *Apar Mukhya Sachiv*.